स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

स्पैक्ट्रम Spectrum

Quarterly House Magazine
Vol. XVII Oct-Dec. 2014

राजभाषा विशेष

Sh. Ved Prakash has taken over as CMD, MMTC

CMD'S MESSAGE

Dear Colleagues,

It is my great pleasure to take over as CMD of MMTC. I wish to thank you all for your good wishes. I am fully convinced and confident that with our collective efforts, hard work and positive outlook, we will steer the company out of the uncertainties seen during last few years and take it to new heights and glory.

Amidst ongoing challenging business environment, we need to redouble our efforts so that we can draw benefit out of our considerable goodwill built over last fifty years, and take the company to new heights. To achieve this goal, on one hand we are focussing on a strategy to strengthen the existing lines of our business activities, while also simultaneously looking for diversification of opportunities in new areas of business keeping in view the suitability with our business model.

I solicit your wholehearted cooperation for transforming MMTC into a new age organisation and one of the best and leading Public Sector organisations of India.

(Ved Prakash)
Chairman and Managing Director

Dated 23.03.2015

Contents

Implementation of the Official Language Policy & Related Guidelines	2
All-India Rajbhasha Conference Conducted at CO	6
MMTC Pays 15% Dividend for 2013-14	7
Celebrations of Vigilance Awareness Week 2014	8
Rajbhasha Event at RO - Bhubaneswar	14
Hindi Week Organized at RO - Bangalore	15
Hindi Event at RO – Jaipur: Crorepati Game Show	16
RO – Goa Organizes Hindi Pakhwada	17
Rashtriya Ekta Diwas at SRO - Kochi	18
Tribute to Sh. V.R. Krishna Iyer	20
Rajbhasha Compliance Inspection at SRO - Kochi	22
Dhanteras at RO - Hyderabad	23
An Overview of INCOTERMS	24
Pure Gold & Silver Gifts	27
Balco Judgement	30
Jurists as SC Judges	32
The Purpose of Trade Unions	36
Goodbye to a Beloved Teacher	40
Dussehra at MMTC Colony	41
Superannuations	42
CMD's Visit to RO Kolkata	44

Corporate Office

Editorial & Production Co-ordinator: Somdutta Sarkar, Dy. Manager (CC)

Editorial Team: Corporate Communication Division

Disclaimer:

The views expressed by the subscribers of various articles in this magazine are their individual views and the editorial team or the organization does not hold responsibility nor endorse the views expressed.

Designed & Printed by : Newfields Advertising Pvt. Ltd.

केंद्र के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा संबंधित दिशानिर्देश

दिनेश कुमार
मुख्य प्रबंधक(राजभाषा)

हिन्दी हमारी मातृभाषा है; मात्र एक भाषा नहीं।

Hkkरत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के पीछे एक कारण यह भी था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देश के कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र देश के लिए एक भाषा, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय झंडे तथा निश्चित भूतल का निर्धारण हुआ। विश्व में स्वतंत्र देश के अस्तित्व का आभास कराने के लिए जिस प्रकार एक राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रगान की आवश्यकता होती है इसी प्रकार एक भाषा की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए स्वतंत्र भारत में जहां तिरंगे को झंडे के रूप में अपनाया गया वहीं हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की स्थिति आज कार्यालयों में जो है वह संतोषजनक नहीं है। हां हम इस बात का संकोच करते हैं कि कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा अलग होती है इसीलिए आज भी हिंदी कार्यालयों में वह स्थान नहीं पा सकी है। वास्तव में भाषा तभी फलती फूलती है जब इसे बोलने वाले बेझिझक अपनाएं। कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोलचाल की भाषा से अलग नहीं होती है। इसलिए निसंकोच उसे लिखना भी प्रारंभ कर दें।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी को महत्व देना रोजाना कार्यालय के कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना तथा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करने पर हमें बल देना होगा। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग बढ़े इसके लिए आवश्यक है कि सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए।

हिंदी भाषा को आम आदमी की भाषा व भारत की एकता का सूत्र बनाते हुए भारत के विकास में इसकी महत्ता को स्वीकारना होगा। अपने कार्यालय के सभी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर देना होगा तथा संवैधानिक दायित्वों को दृढ़ता से निभाना होगा। हिंदी को गौरवपूर्ण स्थान देने के लिए हमें सभी को महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। सरकारी कामकाज में भी हमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

हिंदी भाषा के माध्यम से हमें जीवन व्यवहार के किसी भी पहलू में कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। हम हिंदी के महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। हर भाषा ज्ञान का खजाना है। हर भाषा में कोई न कोई संदेश छिपा है इसलिए अधिकाधिक काम हिंदी में करें। हमें हिंदी के बारे में सकारात्मक सोच रखने से हमारी विचारधारा भी वैसी बनेगी। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को सीखने का समय आ गया है । हम इसे पूरे दिल से अपनाएंगे तभी हम अपना कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे।

हम सभी केंद्र सरकार के उपक्रम में कार्यरत हैं और हमारा दायित्व बनता है

कि इसके कार्यान्वयन में अपना पूरा सहयोग दें ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं नीति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

परिभाषाएं

1. **हिन्दी में प्रवीणता** – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि उसने–

   (i) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है, अथवा

   (ii) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो अथवा

   (iii) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

2. **हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान** – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने–

   (i) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, अथवा

   (ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा

   (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

   (iv) यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) से उद्धरण

उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही–

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी नियम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज–पत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा–प्रारूपों, के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों,

(2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;

(3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

नियम 2 (च) ''क''क्षेत्र से बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं,

(छ) ''ख'' क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं,

(ज) ''ग'' क्षेत्र से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

नियम 8 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना

(1) कोई कर्मचारी किसी फाईल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के

होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

नियम 10 (2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 10 (4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

नियम 11 मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि –

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व–

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह:–

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और,

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें ।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी रिपोर्टों के माध्यम से कई सिफारिशें की गई हैं जिन्हें भारत सरकार ने मान लिया है तथा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(1) मैनुअलों, फार्मों, कोडों आदि की हिन्दी–अंग्रेजी द्विभाषी (डिगलॉट रूप में) छपाई ।

(2) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना ।

(3) हिन्दी में पत्राचार ।

(4) रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाएं।

(5) जांच बिन्दु स्थापित करना ।

(क) लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना

(ख) सेवा पंजी में प्रविष्टियां

(6) हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण को वर्ष 2015 के अंत तक पूरा करना।

(7) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण

(8) हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना ।

(9) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में सहायक/संदर्भ साहित्य, शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

(10) भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिन्दी का विकल्प ।

(11) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं उनकी बैठकें ।

(12) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यों का विस्तार एवं इसकी बैठकों में कार्यालय प्रमुख द्वारा भाग लेना ।

(13) हिन्दी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन ।

(14) हिन्दी कार्यशालायें आयोजित करना ।

(15) सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन ।

(16) गृह पत्रिकाओं/सूचना पत्रों को और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाना ।

कॉरपोरेट कार्यालय में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

महेन्द्र सिंह
वरि.प्रबंधक (राजभाषा)

कॉरपोरेट कार्यालय में राजभाषा अधिकारियों/नोडल अधिकारियों के लिए दिनांक 27–28 नवम्बर 2014 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी नहीं हैं वहां राजभाषा कार्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम डॉ. मदन राय ने क्षेत्रीय कार्यालयों से आए सभी अधिकारियों का स्वागत किया। सम्मेलन का शुभारंभ करते हुये निदेशक (कार्मिक) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से आए सभी अधिकारियों का स्वागत किया। उसके उपरांत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निदेशक (कार्मिक) ने कहा कि राजभाषा हिंदी के अनुपालन और इसके प्रयोग को और गति देने की आवश्यकता है। खुले सत्र में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण पर चर्चा की गई तथा निरीक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझाये गये।

चार सत्रों के पहले सत्र में डॉ. प्रदीप कुमार चौधरी ने राजभाषा अधिनियम/नियम तथा अन्य, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन के दूसरे सत्र में श्री बालमुकुंद ने मानक वर्तनी तथा हिंदी भाषा का स्वरूप और मीडिया पर सारगर्भित व्याख्यान दिया और उपस्थित लोगों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया। कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य के संबंध में श्री संतोष कुमार वर्मा ने विस्तृत रूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया ।

सम्मेलन के अंत में निदेशक (कार्मिक) ने अपने अपने कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निगम में लागू प्रोत्साहन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने की अपील की ताकि अधिक से अधिक कार्मिक हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हो।

श्री मदन रॉय, अपर महाप्रबंधक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

MMTC PAYS 15% DIVIDEND FOR 2013-14

A cheque for Rs.13,48,90,314.30 was presented to Ms. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry by Shri D.S. Dhesi, Additional Secretary, Department of Commerce, then CMD, MMTC towards 15% dividend for fiscal 2013-14. Shri Rajeev Kher, Secretary (Commerce) and Shri Madhusudan Prasad, Special Secretary, Department of Commerce, MOC&I, Shri Ved Prakash, CMD, and the Directors of MMTC were also present on this occasion.

The Company had, at its 51st Annual General Meeting, held on 18th September 2014, declared pay out of 15% for 2013-14 on its paid up equity capital of Rs.100 crores out of the profits of the company for the previous year.

MMTC concluded fiscal 2013-14 by achieving a business turnover of Rs. 25,074.63 which includes Exports of Rs.4,127.02 crore, Imports of Rs.18,713.45 crore and domestic trade of Rs.2,234.15 crore. The Company has been paying Dividend uninterruptedly since 1970. So far the Company has paid a total Dividend of Rs.579.81 crore to Government of India since its inception, apart from issue of Bonus Shares of Rs. 97.00 crores to Government of India.

Combating Corruption – Technology as an Enabler

- Celebrations of Vigilance Awareness Week 2014 in MMTC Ltd.

Laxman Giri
Sr. Manager (Vigilance)

The *Satarkata Saptah* or Vigilance Awareness Week 2014 was observed in all the offices of MMTC Ltd from 27th October to 1st November, 2014. During the week, banners and posters were put up across ROs, the pledge was administered widely in English and in Hindi, messages of Hon'ble President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, and Central Vigilance Commission were publicized, various competitions and presentations were held. The week-long event has gained momentum over the years and the occasion is now celebrated as a collaborative and participative event across MMTC offices in the country.

CORPORATE OFFICE (CO)

The Vigilance Awareness Week 2014 was a grand event at the CO. Alongwith signboards and posters, the messages of Hon'ble President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, and Central Vigilance Commission were displayed at prominent locations within the office premises for viewing by the employees and visitors.

Lighting of lamp by then-CMD Sh. D.S. Dhesi, accompanied by current CMD, Directors and CVO

The Inaugural Function started with the lighting of the lamp by Sh. D.S. Dhesi, then-CMD, Sh. Ved Prakash, current CMD, Sh. Rajeev Jaideva, Director (P), Sh. M.G. Gupta, Director (Finance), Sh. Anand Trivedi, Director (Mktg), Sh. A K Gupta, CVO, and Sh. Sanjay Kaul, GM (Vigilance). Thereafter, floral tribute was offered to the portrait of Sardar Vallabh Bhai Patel, the Iron Man of India. The Pledge, as prescribed by CVC, was administered by Sh. D.S. Dhesi in Hindi, and thereafter by Sh. Ved Prakash in English.

Pledge by Employees at CO

Memento presented to Sh. Mazumdar by Dir (P) Sh. Rajeev Jaideva

Memento presented to Sh. Vij by Dir (F) Sh. M.G. Gupta

A brief speech was delivered by Sh. D.S. Dhesi on this occasion, regarding various forms of corruption. A presentation was made by Ms Anju Gupta, GM (Systems) and Sh. VSN Rao, DGM (IR) on the theme topic 'Combating Corruption – Technology as an Enabler'. The Inaugural Day was concluded by Sh. Sanjay Kaul, GM (Vig) with a Vote of Thanks to the Chair.

During the course of the week, essay and elocution competitions and lectures by special invitees from CVC and APEX (Art of Living) were organized. Sh. Saumitra Mazumdar, Technical Examiner, CVC delivered a presentation on the theme topic with special focus on technology to eradicate the corruption. This was followed by Sh. Ajey Vij from APEX (Art of Living) presenting an informative lecture on "Unlock the Power of Mind". Both the sessions were appreciated by the audience. The guests were welcomed by Sh. Sanjay Kaul and presented with mementos by Sh. Rajeev Jaideva and Sh. M.G. Gupta.

Prizes were distributed by Sh. M G Gupta during the Valedictory Function to the successful participants of all the events. Honorarium was also presented to the judges / evaluators of the Competitions.

During the week, essay writing and elocution competitions were organized in both English and Hindi (and in some offices, in regional languages, eg Kannada, Marathi, etc.) across various offices, which drew considerable participation from the employees.

Essay Writing Topics included

a) Role of Technology in Combating Corruption
b) Corruption: Eating Away from the Inside Out
c) Can Technology Eradicate Corruption?
d) Role of Citizens of India in creating a Swachha Bharat
e) Role of Statutory Agencies viz. CBI, CVC etc in Eradication of Corruption
f) Power Corrupts, but Absolute Power Corrupts Absolutely
g) Corruption: a Cancer, and Ways for its Eradication.

Elocution Topics included

a) An end to corruption is my plan, if you join me friends, I'm sure we can.
b) Anti-Corruption Initiatives from You
c) Scope of Corruption can be Minimized by Technology
d) The Role of Government in Mitigating Corruption
e) Eradication of Corruption.

DRO - JJC

Week long activities were organized in Delhi Regional Office (DRO) and Sub-Regional Offices; Agra, Ludhiana and Kanpur. Sh. Asheesh Majumdar, CGM (JRO), inaugurated the celebrations and administered the pledge in English, while Sh. Satish Kumar, VO, administered the pledge in Hindi. Sh. Majumdar gave a brief speech on the occasion. Essay writing and Elocution competitions were conducted for the officials during the week. Before the valedictory ceremony, a documentary on Sardar Vallabh Bhai Patel was screened. Sh. Majumdar distributed prizes to the winners of competitions, and extended his wholehearted support for the successful celebration of the Week.

RO: JAIPUR

At RO Jaipur Sh. Sanjeev Dua, GM, administered the pledge to all employees. Essay and Elocution competitions were organized, in which nearly all the employees participated. Sh. Jagdish Prashad, DSP, CBI, Jaipur was invited as Chief Guest, who delivered a speech on the theme topic before conclusion of the Week.

RO: AHMEDABAD

A welcome address was delivered by Sh. Deepak Pitlawar, VO, followed by the pledge (English) read by Sh. Manohar Babu, GM and the pledge (Hindi) read by Sh. S S Modh, AGM.

Pledge Ceremony at RO- Ahmedabad

All the employees below the rank of DGM participated in the Essay and Elocution competitions held during the week. The prizes were distributed to the winners during the Valedictory Function by Sh. S S Modh & Sh. V.W. Singh(Sr. Mgr.). Sh. Modh addressed the officials and spoke on how to be vigilant in day-to-day office activities.

RO: GOA

The weeklong programme at RO Goa was inaugurated by Sh. V.K. Chowdhary, GM, by lighting the traditional lamp. Sh. Chowdhary and the Vigilance Officer addressed the audience and highlighted the aim and importance of Observance of Vigilance Awareness Week.

Pledge Ceremony at RO- Goa

A special lecture-and-discussion was organized on the theme of the week, wherein all the officers and staff enthusiastically participated. Essay and Elocution competitions were also held during the week. Sh. Sharad Chopdekar, Ex-Chairperson & presently Councilor of the Mormugao Municipal Council, was invited as the Chief Guest for the Valedictory Function.

RO: MUMBAI

The Vigilance Awareness Week at RO Mumbai began with the pledge administered by Sh. A Sondhi, CGM, and the lighting of the inaugural lamp by Chief Guest Sh. Swapan Garain, Professor, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Sh. Garain addressed the audience on the theme topic of the importance of technology in combating corruption. Sh. P. Ramachandran, GM, also spoke on combating corruption being a collective responsibility.

Sh. H K Jawale, IAS, Commissioner of Labour, Maharashtra State, was invited as Chief Guest for the Valedictory Function. Sh. P Ramachandran had summarized the sessions by emphasizing the importance of technology in our trading operations. The Chief Guest mentioned in his address that

Vigilance Awareness program at RO- Mumbai

combating corruption requires multifaceted efforts. He also awarded prizes to the winners of the Essay and Elocution competitions held during the week.

RO: KOLKATA

At RO Kolkata, Sh. Ajit Kumar Khan, IRS, Addl. Commissioner of Income Tax was invited as Chief Guest for the inauguration of the Vigilance Week, which commenced with welcome speech by VO and lighting of the lamp by the Chief Guest. The Pledge was administered by Sh. J Kishan, CGM, in English and by Sh. B K Jha, Chief Manager, in Hindi.

On the Valedictory Day, Sh. P K Panigrahi, SP, Anti-corruption Branch, CBI was the Guest Speaker. He described in detail how the anti-corruption cell and investigating agencies are utilizing the modern latest technologies to detect and eradicate corruption. Thereafter, prizes were distributed to winners of the essay and elocution competitions held during the week. Sh. K K Pal, GM, gave the vote of thanks for the successful completion of the Satarkata Saptah.

Pledge Ceremony at RO- Kolkata

Vigilance Awareness Week was also observed in SROs Haldia and Ranchi.

RO: BHUBANESWAR

The Vigilance Awareness Week was inaugurated by Sh. T.K. Sengupta, GM, with the pledge being administered to all employees, Sh. Sengupta explained the highest ideals of integrity, ethics and best values in the Indian tradition with reference to corporate governance, and advised the employees to work in a transparent manner and to strengthen preventive vigilance by streamlining systems and simplifying procedures.

Dr G K Panda, Professor of Geography & Chairman - PG Council, Utkal University, Bhubaneswar, was invited as Chief Guest for the Valedictory Function. His address touched upon topics like corruption prevalent in India & other countries, powers delegated to employees of the private and govt. sector, the need of transparency in all official transactions, and the importance of motivation and self introspection along with information technology & communication in combating corruption. Sh. Sengupta, in his speech, emphasized upon the need to work with dignity, honesty and sincerity. He also remained actively involved in the programmes and gave valuable suggestions at every stage to make the week a success.

Vigilance Awareness functions were also organized at SROs Barbil and Paradeep, and in MMTC Cell Duburi and Puri Sales Outlet. For the valedictory progamme at SRO Barbil, Sh. A.P. Swain SDPO, Barbil was invited as the Chief Guest, who highlighted in his speech the need of vigilance and the utility of Vigilance Awareness Week.

RO: VIZAG

GM Sh. S.K. Das presided over the inaugural function, and His Holiness, Swami Nitya Yogananda of Ramakrishna Mission was invited as the Chief

GM Sh. S.K. Das presenting memento to Chief Guest.

Guest. Our national leaders including Sardar Vallabh Bhai Patel were honored with garlands to their portraits. Sh. Das administered the pledge and emphasized the need for detachment from worldly needs which are primary cause of corruption.

Swami Nitya Yogananda Ji in his address dealt at length with the cultivation of ethical values and endeavours to bring change in the society. Though technology can aid in combating corruption, technology may become redundant sometime, he said, adding that distinction between good and bad is a gift from God given to mankind and it must be exercised properly.

During the week, presentations were made my Divisional and Profit Centre Heads on their areas of operations with a vigilance angle in view. Aside from essay and elocution competitions, a brief session was also organized to discuss the theme topic of the Week.

RO: CHENNAI

The inaugural function began with Sh. A Radhakrishnan, AGM (P) administering the Pledge in English and Sh. V Murali, AGM (F&A) leading the Pledge in Hindi. Sh. J.V.N Rao, GM, took an interactive session later in the week wherein he advocated the need for prudence in our actions and also quoted verses from Upanishad and Sanskrit about the dangers of corruption and greed.

Pledge Ceremony at RO- Chennai

On the valedictory day, Sh. V Gunasekhar, Indian Telephone Service Officer of 1985 batch serving as Chief General Manager of Bharat Broadband Network Limited, Chennai was invited as Chief Guest. Sh. Gunasekhar spoke on the theme topic and also about the ICT, mobile technology, media, social media, CCTV, IPV-6, e-procurement, e-billing, e-payment, etc. He also distributed prizes to the winners of Essay and Elocution competitions held during the week. A Memento was presented to the Chief Guest by Sh. Rao.

Vigilance Awareness activities were also held at SRO Kochi.

RO: BANGALORE

The inauguration of the Week was done by GM Sh. T. D. Suresh Babu who administered the pledge to all employees. Other Sr. Officers and Representatives of Officers Associations, Employees' Union and WIPS also participated in the inauguration. Sh. Suresh Babu, in his address, focused on the

Valedictory Function at RO- Bangalore

Pledge Ceremony at SRO- Bellary

theme of the Week and expressed that effort is to be made for reducing human intervention to a minimum level in all day-to-day activities of governance.

A guest lecture was organized on the theme of the Week and Sh. S Balaji, Ph.D, Ex-Professor of ISRO, was invited as the Guest Speaker. Sh. Balaji discussed how technology can help in reducing corruption by enabling transparency, accessibility, and awareness.

His Holiness Sh. Varada Krsna Dasa, B.E, MBA of ISKCON, Bangalore graced the Valedictory Function as Chief Guest along with another ISKCON devotee. The function commenced with a prayer and Sh. Suresh Babu presided over the occasion. He also reviewed the weeklong programs and activities in his valedictory address, while His Holiness used a PowerPoint presentation to play a number of evocative video clippings for better understanding of the subject.

The Prizes to the winners and participants of competitions held during the Week, as well as honorariums/ mementoes to Judges and Coordinators were distributed by the Chief Guest. Sh. P. Thangavel, DGM (P&A), gave the Vote of Thanks. Vigilance Awareness events were also organized at SRO Bellary during the week.

RO: HYDERABAD

Sh. TS Rao, GM, presided over the inauguration function and

Pledge Ceremony at RO- Hyderabad

administered the pledge to the employees. Director (Personnel), in Hyderabad at the time, graced the occasion as Chief Guest while Sh. TS Rao, GM, administered the pledge to all the employees. The function commenced with lighting of lamp by the GM and Senior Officers.

Sh. Rao addressed the gathering about the Week's theme of technology against corruption and urged all the officials to acquaint themselves with the latest technology i.e. ERP systems, policies/procedures/ drills of the various commodities, etc.

The birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel was celebrated as "Rashtriya Ekta Diwas" and a pledge was taken on the occasion. On the Valedictory Day, Sh. Rao presided over the function and distribution of prizes to winners of various competitions. Sh. C.M. Purty, AGM (I/A) gave a lecture on the importance of vigilance and how to be vigilant in our day to day's work.

With a vote of thanks, the week-long programme was concluded successfully.

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित राजभाषा कार्यशाला

उत्पल चाटार्जी
उप प्रबंधक (विपणन/राजभाषा)

दिनांक 16.12.2015 को एमएमटीसी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में राजभाषा कार्यशाला मुख्य प्रबंधक स्तर तक के सभी कार्मिकों के लिए आयोजन किया गया था। श्रीमती बेबी रानी मिश्र, राजभाषा अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, भुवनेश्वर को कार्यशाला संचालन हेतु बुलाया गया । श्री टी. के. सेनगुप्ता, महाप्रबंधक ने सभी उपस्थित कार्मिकों का स्वागत करते हुए राजभाषा कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया और हिन्दी में काम काज करने को आह्वान किया। तत्पश्चात्, श्रीमती बेबी रानी मिश्र ने राजभाषा के धारा 3(3) नियम और अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में विभागीय टिप्पणियों का लेखन, ज्ञापन, आदेशों, परिपत्रों, छोटे पत्रों को हिन्दी में प्रेषण करने और कम्प्युटर पर इंटरनेट के सहारे हिन्दी काम काज करना कितना आसान है उसका तकनीकि बताया। कार्यशाला में नामित कार्मिकों ने सोत्साह कार्यक्रम में भाग लिया।

अंत में, श्री उत्पल चाटार्जी, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा धन्यवाद के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई।

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरू में आयोजित हिन्दी सप्ताह

मधुलिका मिश्र
उप प्रबंधक (कार्मिक)

विगत वर्ष की तरह ही क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरू में हिन्दी सप्ताह नवंबर 2014 में बेंगलूरू, बेल्लारी तथा होसपेट क्षेत्र में मनाया गया।

प्रथम चरण में बेल्लारी तथा होसपेट क्षेत्र में हिंदी कार्यक्रमों तथा निबंध लेखन तथा संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेल्लारी तथा होसपेट में 20 कर्मचारियों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। जबकि संभाषण प्रतियोगिता में 5 कर्मचारियों ने भाग लिया। बेल्लारी होस्पेट में आयोजित कार्यक्रम में कार्यालय के अधिकतम कर्मचारी शामिल हुए और कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सा लिया। समारोह का शुभारंभ करते हुए श्रीमती मधुलिका मिश्र ने सबका स्वागत किया और मुख्य अतिथि, उप महाप्रबंधक श्री पी थंगवेल (राजभाषा), तथा श्री सी एम कामोजी, कार्यालय प्रभारी, बेल्लारी को मंच पर आमंत्रित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और निर्णायक के रूप में श्री विजय कुमार, एम कॉम, एम ए हिंदी, अवकाश प्राप्त हिंदी प्रोफेसर, अल्लुपम सुमनगलम्मा महिला कॉलेज, बेल्लारी आमंत्रित थे। उन्होंने इस अवसर पर समारोह को संबोधित किया और हिंदी की राष्ट्रीय भूमिका के बारे में वक्तव्य रखा। समारोह को श्री पी थंगवेल और श्री सी एम कामोजी ने भी संबोधित किया। श्रीमती मधुलिका मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। विजयी प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि, श्री सी एम कामोजी, श्री पी थंगवेल, के हाथों से नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी सप्ताह के कार्यक्रम में भाग लेने वाले शेष सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

द्वितीय चरण में बेंगलूरू कार्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता और संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में 7 कर्मचारियों ने भाग लिया जबकि संभाषण में 3 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के निर्णायक और मुख्य अतिथि के रूप में श्री एम पी दामोदरन, बी ए हिंदी (गोल्ड मेडल), एम ए (हिंदी) तथा अनुवाद का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बी एड, सहायक निदेशक (भाषा) राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उपसंस्थान, बेंगलूरू उपस्थित थे।

समारोह की शुरूआत श्रीमती मधुलिका मिश्र के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अधिकारियों का समारोह में स्वागत किया और कार्यालय में हिंदी में किए जा रहे कार्यों और हिंदी सप्ताह के महत्व से सबको अवगत कराया। समारोह में श्री के लगुमराजू ने एक स्वागत भक्ति गीत प्रस्तुत किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री टी डी सुरेश बाबु ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की पृष्ठभूमि और उसे राजभाषा बनाए जाने के घटनाक्रम पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए श्री एम पी दामोदरन ने कहा कि हिंदी के द्वारा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। हिंदी भाषा पूरे देश में बोली और समझी जाती है और यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है।

निबंध लेखन और संभाषण प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों को नगद प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मधुलिका मिश्र ने किया। श्री थंगवेल ने हिंदी के दैनिक कार्यों में सबके सहयोग की अपील की तथा समारोह में सक्रिय भागीदारी के लिए सबको धन्यवाद दिया।

हिंदी पखवाड़ा जयपुर – विजेता बना 'करोड़पति'

विजय कुमार सहगल
उप प्रबंधक (राजभाषा)

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा के दौरान 'कौन बनेगा विजेता' नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता एक खेल के रूप में थी, जिसे कंप्यूटर पर पॉवर प्वाइंट प्रोग्राम में बनाया गया था। इसके लिए स्लाइड्स पर प्रश्न अंकित किए गए थे। प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर थे। हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागी को सही उत्तर बूझना था। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाता। जो प्रतिभागी जितने अधिक सही उत्तर बूझता वह उतने अधिक अंक पाकर बड़े पुरस्कार का अधिकारी था।

प्रतियोगिता में राजभाषा नियम, अनुवाद, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया था। इसमें वरिष्ठ प्रबंधक स्तर तक के सभी कार्मिकों ने भाग लिया। अपर महाप्रबंधकों ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभायी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महाप्रबंधक श्री संजीव दुआ ने की।

हॉट सीट का एक दृश्य

प्रतियोगिता के लिए हॉट सीट पर आने का एक खास नियम बनाया गया था। नियम के अनुसार कंप्यूटर पर स्लाइड दिखायी जाती जिसपर एक प्रश्न अंकित होता। जो प्रतिभागी उस प्रश्न का उत्तर बूझकर खेल को शुरू करना चाहते थे, वे अपना हाथ उठाकर इशारा करते थे। जो सबसे पहले इशारा करता, वह हॉट सीट पर आने का मौका पाता था। हॉट सीट पर आने के साथ मन में एक सवाल भी रहता कि आगे की स्लाइड्स पर कौन–कौन–से प्रश्न आएंगे, और कितने प्रश्नों के सही उत्तर बूझने में कामयाबी मिलेगी। मनोरंजन, ज्ञान, उत्सुकता और कौतूहल से भरपूर इस प्रतियोगिता का सभी ने भरपूर आनंद लिया। प्रतियोगिता में श्री सुनील कुमार काला, श्री कमल सूद, श्री एम एल पाण्डे, श्री पी. के. सिद्धार्थ, और श्री प्रकाश विजेता रहे।

महाप्रबंधक श्री संजीव दुआ का संबोधन

अंत में महाप्रबंधक महोदय ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और इस अनूठे कार्यक्रम को तैयार करने के लिए उप प्रबंधक (राजभाषा) को शाबाशी दी।

गोवा में हिंदी फखवाड़ा समापन समारोह

गोवा कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

मंदा अरूण वल्वईकर
व. का. प्रबंधक (राजभाषा)

Xkवा क्षेत्रीय कार्यालय में सितंबर, 2014 में आयोजित हिंदी पखवाड़े के दौरान विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे निबंध प्रतियोगिता, श्रुत लेखन प्रतियोगिता इत्यादि। निबंध प्रतियोगिता का विषय था– **समाचार चैनलों के बीच फंसी बेचारी जनता।** इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय कार्यालय के 7 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के विजेता थे श्री सोना शिरोडकर, वकाप्र/निजी सचिव, श्री लक्ष्मण पोरोब, प्रबंधक, और सुश्री माला दाभोलकर, वकाप्र। श्रुत लेखन प्रतियोगिता में लगभग गोवा क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

समापन समारोह श्री वी. के. चौधरी, महाप्रबंधक, की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुश्री मंदा वल्वईकर ने स्वागत भाषण में सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए संक्षिप्त में हिंदी पखवाड़ा मनाने के मुख्य उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को तथा सहभागियों को उत्साहित करने तथा हिंदी भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए नकद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया।

अंत में अपने संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने पिछले साल से ज्यादा सहभागियों की बढ़ती संख्या को देखकर संतोष प्रकट किया और हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में नई–नई प्रतियोगिताएं आयोजित करके हिंदी भाषा को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को नए विचार तथा सुझाव देने के लिए अनुरोध किया ताकि अगले हिंदी पखवाड़े मे विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके।

अंत में श्री मनोज बसाक, वरिष्ठ प्रबंधक (सिस्टम्स/प्रशासन) एवं हिंदी नोडल अधिकारी ने इस पखवाड़े को सफल बनाने एवं उनके योगदान के लिए सभी कार्मिकों को धन्यवाद दिया।

बधाई

हिंदी सप्ताह समापन के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशासन विभाग की ओर से मुख्य अतिथि एवं गोवा क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी महाप्रबंधक श्री वी. के. चौधरी ने एमएमटीसी में 30 साल की दीर्घकालीन सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी श्री वल्लभ प्रभु देसाई, वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी, को पुष्पगुच्छ तथा सौ ग्राम चाँदी का सिक्का प्रदान करके सम्मानित किया।

एमएमटीसी परिवार की ओर से श्री वल्लभ प्रभु देसाई को हार्दिक बधाई।

दीर्घकालीन सेवा के लिए श्री वल्लभ प्रभु देसाई को सम्मानित करते हुए श्री वी.के. चौधरी

Pledge being administered by Sh. R.K. Arvind, AGM

Rashtriya Ekta Diwas

Amal M.
Dy. Manager

The culture of India has been shaped by its long history, unique geography and diverse demography. The term multiculturalism is not often used but the phrase "unity in diversity" is highly popular and much appreciated. India's languages, religions, art, architecture and customs differ from place to place within the country, but nevertheless possess a commonality. Home to more than 1652 languages,

"Manpower without Unity is not a strength unless it is harmonized and united properly, then it becomes a spiritual power."

India is culturally, linguistically, religiously and to a certain extent, ethnically, the most diverse country in the world.

Focusing on the unified diversity of the nation, the current government announced the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel (October 31st), be celebrated as Rashtriya Ekta Diwas (National Integration Day) every year starting from 2014. *"The birth anniversary of Sardar Patel will provide all of us an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country,"* said Shri Rajnath Singh, Union Home Minister.

The 'Run for Unity' event was the key highlight of the elaborate celebrations organized by the government to observe *Rashtriya Ekta Diwas* to pay tribute to the efforts made by Sardar Patel to unite India. Flagging off the 'Run For Unity' on the occasion of Sardar Patel Jayanti, the Prime Minister, Shri Narendra Modi, recalled the mantra of "Ek Bharat: Shresth Bharat" and said that Sardar Vallabhbhai Patel gave us "Ek Bharat" (United India), and we should all work towards creating "Shresth Bharat" (Foremost India).

The Iron Man of India

Sardar Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, 'The Iron Man of India' was born on 31st October, 1875, in a small village in Nadiad. His father Jhaverbhai Patel was a simple farmer and mother Laad Bai was a simple lady. From his childhood itself, Patel was a hardworking individual. He used to help his father in farming and studied in N. K. High School, Petlad. He was an intelligent student and passed his high school examination in 1896. Despite their poor financial conditions, his father decided to send him to college, but Vallabhbhai refused. He stayed home for around three years, worked hard and prepared for the District Leader's examination, and passed them with very good percentage.

A barrister with a successful law practice, Vallabhbhai Patel joined the Indian National Movement under Mahatma Gandhi and grew to become one of its foremost leaders. He played a key leadership role in organizing peasants' movements in Kheda, Borsad and Bardoli in Gujarat, and in promoting the Quit India Movement against the British Raj. The British government considered him a threat and his lectures were considered anti-government and he was imprisoned several times.

Patel's presidential address to the Congress in 1931 included these highly inspiring lines: "No one would die of starvation in independent India. Its grain would not be exported. Cloth would not be imported by it. Its leaders would neither use a foreign language nor rule from a remote place 7,000 feet above sea level. Its military expenditure would not be heavy. Its army would not subjugate its own people or other lands. Its best-paid officials would not earn a great deal more than its lowest-paid servants. And finding justice in it would be neither costly nor difficult."

The credit for the integration of over 500 independent princely states in 1947-49 through their merger from what was then a divided India to make it what it is today is due solely to Sardar Vallabhbhai Patel. Despite the choice of the people, on the request of Mahatma Gandhi, Sardar Patel stepped down from the candidacy of Congress president. The election on that occasion eventually led to the election of the first Prime Minister of Independent India.

In 1991 the grateful nation conferred upon him the honour of Bharat Ratna. Today, 67 years after independence, India desperately needs a leader like Sardar Vallabhbhai Patel, who was not just an inspiration but also a torchbearer who showed us that integration of Indians is only possible with the spirit of co-existence.

Tribute to the 'Epitome of Justice' Sh. V.R. Krishna Iyer

M. R. Guru Prasad & Santosh J Chitari
Manager Dy. Manager

AGM Sh. R.K. Arvind & Manager Sh. M.R. Guruprasad along with late Justice V.R. Krishna Iyer

Vaidyanathapura Rama Krishna Iyer (born 15 November 1914), popularly known as Justice V. R. Krishna Iyer, is a former judge of the Supreme Court of India. He was born at Vaidyanathapuram near Palakkad, in Malabar region of Kerala, but grew up at Koyilandy, also in the erstwhile Malabar district. In 1952, he was elected to the Kerala Legislative Assembly, and in 1957, he became a minister in the first Communist government in Kerala, serving until 1959. Having been the minister of law, power, prisons, irrigation and social welfare in the Government of Kerala, he was instrumental in bringing about many significant changes in these sectors. In 1973, he was sworn in as a Judge of the Supreme Court of India; as of 2011, he is the last but one Supreme Court judge to have previously served as a politician. He was conferred with Padma Vibhushan in the year 1999.

In June 2008, Shri Iyer had been among several leading jurists and civil rights activists who signed an open letter urging Iran to abide by international human rights conventions and release the detainees of the leadership of the Bahá'í Faith in Iran. In July 2010, Shri Iyer supported a campaign to introduce Islamic banking and finance into India. "I welcome Islamic finance in India. Islamic finance has proven successful in poverty alleviation and promoting sustainable growth in many countries, including the United States, and it is very relevant in our country where 20 million people are starving," he said.

Justice Iyer is also serving as the President of Kerala Janakeeya Prathirodha Samithi, a state level organisation in Kerala, which is leading and coordinating various mass movements and anti globalization movements in the state. Born in Palakkad in Kerala, Justice Iyer made the unusual transition from politician to judge - he was a legislator and the law minister in 1957 in Kerala's first Left

government. In 1968, he became a judge in Kerala before being appointed to the Supreme Court in 1973.

Justice Iyer is often referred to as the "man who triggered the Emergency." On June 24, 1975, he refused an unconditional stay on an Allahabad High Court verdict holding then-Prime Minister Indira Gandhi guilty of electoral malpractices and invalidating her election. The next day, Smt. Indira Gandhi declared Emergency.

His lonely crusade against the death penalty would lead to a later bench of the court letting it be imposed only in the "rarest of rare" cases. He made bail conditions humane and directed the government to provide free legal-aid to detainees facing charges in prisons, once ruling that: "Bail is the rule, and jail, the exception".

Along with Justice P. N. Bhagwati, he laid the foundations for the induction of PILs (Public Interest Litigations) in a country with a series of cases, when in one such case, he treated a prisoner's letter posted from jail as a writ petition, commenting: "Freedom behind bars is part of our constitutional tryst... If wars are too important to be left to the generals, surely prisoners' rights are too precious to be left to the jailors."

Famous not only for his fair judgements but also for his mastery over the English language and his use of it in his judgements, Justice Iyer retired from the Supreme Court in 1980.

"Warm birthday wishes to an icon in Indian public life, Justice V R Krishna Iyer, as he turns 100. I pray he is blessed with good health,"

-Prime Minister Sh. Narendra Modi

In the early hours of November 15, 2014, Sh. R.K. Arvind, AGM/In-charge (SRO Kochi), visited the residence of Justice V R Krishna Iyer, presented him a bouquet and greeted him on the special occasion of his 100th birthday on behalf of MMTC. The idea was to recognize and respond favourably to the sentiments of Kochi Town, which regards Justice V R Krishna Iyer as a favourite leader and the Jurists therein have been appealing to the President and Prime Minister to confer the Bharat Ratna on this great leader.

People from various walks of life recalled Shri Iyer's multi-faceted roles as an eminent jurist, legislator, and human rights crusader, at the event organised by the People's Council for Social Justice (PCSJ) at T.D.M. Hall, Ernakulam. Another function saw 100 balloons being released to celebrate the jurist's centenary. In the absence of the Chief Minister, Minister for Excise Ports Sh. K. Babu presided over the function. Shri Iyer had been a crusader for social justice and causes even in the final days of his life. The legal luminary was admitted to the hospital on November 24 in connection with age-related ailments. His blessed soul passed away on Dec 4, 2014 due to multiple organ failures.

उप–क्षेत्रीय कार्यालय कोची में राजभाषा अनुपालन के तहत निरिक्षण

संतोष जे. चितारी
उप प्रबंधक

निरिक्षण के समय कार्यालय प्रधान श्री आर. के. अरविन्द के साथ राजभाषा प्रभारी श्री संतोष जे. चितारी, उप प्रबंधक, और कॉर्पोरेट कार्यालय के निदेश के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के राजभाषा अधिकारी श्री अर्जुन इंदवार, प्रबंधक (राजभाषा) भी उपस्थित थे निरिक्षण टीम को कार्यालय में हिंदी सम्बन्धी कार्यकलापों से अवगत कराने के लिए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के राजभाषा निदेशक श्रीमती देवकी और उप निदेशक (राजभाषा) श्रीमती संतोष शिल्पोकर ने दिनांक 18.11.2014 को एमएमटीसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय कोच्ची का निरिक्षण किया। वाणिज्य मंत्रालय के दोनों अधिकारियों ने कोच्ची कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरिक्षण किया और कार्यालय में किये हुए कार्य पर समाधान व्यक्त किया।

सर्वप्रथम दोनों अधिकारियों का कोच्ची कार्यालय प्रधान ने फुलों के गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके उपरांत राजभाषा निदेशकों की टीम ने कार्यालय में उपलब्ध राजभाषा कार्य के सम्बन्धी सभी कागजात एवं दस्तावेज, जैसे पत्राचार, टिप्पणियाँ आदि का ध्यान से निरिक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन पर कार्यालय प्रधान अपर महाप्रबंधक श्री आर. के. अरविन्द के साथ विस्तृत रूप में वार्तालाप किया।

कोच्ची के उप क्षेत्रीय कार्यालय ''ग'' क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ अधिकतर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं और हिंदी में पत्राचार किया जाता है। यहाँ कार्यालय के सभी नाम पटल, लेखन–सामग्री, रबड़ मोहरें आदि द्विभाषी हैं और हिंदी प्रभारी के अलावा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी गूगल अनुवाद और युनिकोड ट्रांस्लिटरेशन के सहायता से हिंदी में अपने कुछ कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। कार्यालय के पटल पर रोज एक हिंदी का शब्द लिखा जाता है जिससे कर्मचारियों को हिंदी शब्दों का ज्ञान मिलता है। कार्यालय में अधिकतर सभी बैठकों में हिंदी में ही वार्तालाप एवं चर्चा होती हैं। हिंदी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए श्रीमती देवकी महोदया ने बताया की एमएमटीसी कोच्ची के कार्यों को देखते हुए वे संतुष्ट हैं और इसी को बरकरार रखने के लिए सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रोस्ताहित किया और बताया की भविष्य में वे कार्य की प्रगति का निरिक्षण करने के लिए पुनः कोच्ची कार्यालय में आने का प्रयास करेंगे।

Dhanteras at RO - Hyderabad

S. Rahim Basha
Dy. Manager (Vig)

On the eve of Dhanteras, as per precedence, sale/exhibition was organized at RO-Hyderabad for a period of two weeks. The event was given wide publicity in all the leading national daily newspapers. It was inaugurated by lighting of the traditional lamp by Shri T.S. Rao, GM, alongwith Shri S. Bobanga, GM (F&A) and Shri Inder Singh, Ex-officio O/O Central Vigilance Commission, who graced the function by their presence. There was a highly positive response to this exhibition. A similar event was also organized for two days in Cyber Towers of Hitech city, Hyderabad in the L&T Info city for promoting sales. The target of sales worth Rupees one crore was achieved and Hyderabad RO has consequently done a total business of INR 1.36 Crores during this exhibition. It is the collective effort of the officers and staff of the RO, under the dynamic leadership of senior officers, that the given target could be achieved and the sale-exhibition was a grand success.

Sh. Inder Singh, Ex-Officio, CVC, lighting the lamp

Sh. T.S. Rao, GM- RO Hyderabad, inaugurating the exhibition

An Overview of INCOTERMS

M. K. Suryanarayanan
Ex-Senior Manager

The International Commercial Terms (INCOTERMS), evolved by International Chamber of Commerce (ICC) provides a set of rules for international trade contracts. INCOTERMS define the respective obligations, costs and risks involved in the delivery of goods from the seller to the buyer. It supersedes the law governing a contract and defines where titles transfer and does not address the price payable, currency or credit terms. INCOTERMS are revised from time to time to suit changes in international trade and practices, some by Governments, and subtle changes and practices like string sales by the international trading community.

INCOTERMS are (a) limited to rights and obligations of parties to a contract of sale, (b) have no relations to other contracts required for international sales, such as contracts of carriage, insurance and financing (however, choosing a particular incoterm has an implication on these contracts), and (c) deal only with specific terms of contract of sale such as packing, clearance, transportation and delivery of goods.

The earlier version of INCOTERMS (i.e. 2000) contained 13 delivery terms. The latest version of the INCOTERMS has only 11 terms, four terms having been omitted and two terms have been added.

The INCOTERMS have been divided into four groups. The first word of each group stands for the Group. These groups are:

Group E (one term) Ex Works – named place

Group F (three terms)	i.	FCA (free carrier) - named place
	ii.	FAS (free alongside) - named port of shipment
	iii.	FOB (free on board) – named port of shipment
Group C (four terms)	i.	CFR (cost & freight) - named port of destination
	ii.	CIF (cost, insurance & freight) – named port of destination
	iii.	CPT (carriage paid to) – named place of destination
	iv.	CIP (carriage & insurance paid to) – named place of destination.
Group D (three terms)	i.	DAT (delivery at terminal) – named place of terminal
	ii.	DAP (delivery at place) - named place
	iii.	DDP (delivered duty paid) – named place of destination

The terms in brief:

- **Group 'E'**

EX WORKS (named place) - may mean any place of work like Ex-Factory, Ex-Mill, Ex-Plantation, or Ex-warehouse. This term generally includes the price of the product, cost of packing suitable for the mode of transport. Ex-Works means that the seller places the goods at the disposal of the buyer at the named place. He is not under any obligation to load the goods on to the means of transport employed by the buyer. Also, the seller is not bound to get export clearance. Seller's responsibilities are over the moment he places the goods at the disposal of the buyer. This term can be used for all modes of transport.

- **Group 'F'**

FREE CARRIER (FCA) (named place) - means that the seller delivers the goods cleared for export to the carrier nominated by the buyer at the named place and he is responsible for loading of the goods on the means of transport provided by the carrier. If the delivery occurs at any other place, then the seller carries the goods by his means of transport and places at the disposal of the carrier, without unloading them. The seller's risk and responsibilities ceases the moment he delivers the goods at the nominated place or point to the charge of the carrier.

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) (named port of shipment) - means that the seller delivers, cleared for export, when the goods are placed alongside the vessel at the named port of shipment. The price quoted under this contract includes charges up to placing the goods alongside the ship in the seller's country. In FAS, the buyer has to arrange for carriage. The seller's responsibilities ceases the moment he places the goods alongside the vessel. From this point, the buyer has to bear all the costs and risks of loss or damage to the goods. The term can be used for sea or inland waterways transport.

FREE ON BOARD (FOB) (named port of shipment) - means that the seller delivers when the goods pass the ship's rails at the named port of shipment. The price quoted under this contract includes charges up to preparation of goods for export and placing them on board the named vessel in the seller's country. Seller's responsibilities ceases the moment the goods pass the ship's rail at the named port of shipment.

- **Group 'C'**

COST AND FREIGHT (CFR) (named port of destination) - means that the seller delivers when the goods pass the ship's rail in the named port of shipment. The seller must pay the cost and freight necessary to bring the goods to the named port of destination. In such contracts, the port of discharge should be mentioned.

A CFR contract is slightly tricky to understand. Though the seller pays charges upto destination, the risk or loss or damage to the goods passes on to the buyer the moment the goods cross the ship's rail and

are on board of the ship in the seller's country. The seller bears the cost upto the destination, but the buyer acquires the interest in the goods the moment they are loaded on board the ship in the seller's country. This term is used for sea and inland waterways transport.

COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) (named port of destination) – implies that the seller delivers when the goods pass the ship's rail in the origin port. The seller has to arrange for carriage and insurance. Simply put, CIF includes FOB price plus cost of ocean freight and marine insurance upto the port of destination. The risk in the goods passes on to the buyer the moment they are placed on board a vessel in the seller's country.

CARRIAGE PAID TO (CPT) (named port of destination) - Under CPT, the seller delivers the goods to the carrier (arranged by him) and pays the freight for the goods carriage to the named port of destination. The buyer is not under obligation of contract for insurance. Risk is passed on to the buyer when the goods have been delivered to the carrier.

CARRIAGE & INSURANCE PAID TO (CIP) (named place of destination) - The seller has the same obligation as under CPT but, additionally has to procure cargo insurance on the minimum cover against the buyer's risk of loss or damage to the goods during transportation. The seller has to pay all the cost relating to the goods to the destination. It may be noted that if more than one carrier is used for the carriage of goods to the agreed destination, then the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

DELIVERY AT TERMINAL (DAT) (named place of terminal) - provides for delivery of goods, unloaded from the arriving means of transport and placed at the disposal of the buyer at the named terminal. Terminal would include any place like quay, warehouse, container yard or road, rail or air cargo terminal. Seller is responsible for the costs and risks of bringing the goods to the point specified in the contract.

DELIVERY AT PLACE (DAP) (named placed) - means that the seller delivers when the goods are placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport. In this, the seller's responsibilities ceases once the goods are brought to the named place. The parties are advised to specify as clearly as possible the terminal and if possible, the exact point within the terminal at the agreed port or destination as all risks to that point are to the account of the seller.

DELIVERED DUTY PAID (DDP) (named place of destination) - means that the seller delivers the goods and places at the disposal of the buyer, cleared for imports on the arriving means of transport, ready for unloading at the named place of destination. In this the seller bears all the risk and cost involved in transporting the goods to the named place of destination. He also bears the obligation to clear the goods not only for export from his country (which means paying export duty, mandatory inspection charges, taxes, etc.) and to clear the goods for import at the named place of destination by paying all charges and obtaining customs clearance for import into the country. DDP represents the maximum obligation for the seller.

शुद्ध सोने व चांदी के उपहार, बने रहें हमेशा यादगार

हरदयाल सिंह
प्रबंधक (राजभाषा)

भारत के बुलियन (बहुमूल्य धातु) व्यापार में एमएमटीसी लिमिटेड मार्केटिंग लीडर के रूप में प्रतिष्ठित है। एमएमटीसी का क्षेत्रीय कार्यालय झंडेवालान, नई दिल्ली अपने ब्रांड के सोने व चांदी के मेडालियन/सिक्कों का 1996 से उत्पादन कर रहा है। सोने व चांदी के मेडालियन/सिक्कों का उपयोग कार्मिकों को दिये जाने वाले सेवा अवार्ड के रूप में कई कार्यालयों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, देना बैंक, रेलवे प्रणाली सूचना केंद्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे आदि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के कॉरपोरेट/संस्थागत आर्डरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर पूरा किया जाता है।

स्वर्ण/सोना

स्वर्ण एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह ए.यू. (Au) है और परमाणु संख्या 79 है। कई शताब्दियों से इस बहुमूल्य धातु को संपत्ति के रूप में, आभूषणों के रूप में संचय कर रखा जा रहा है। यह धातु चट्टानों में ग्रेन्स के रूप में पाया जाता है, भूमिगत सतहों में और कछारी भूमि में डिपॉजिट्स के रूप में पाया जाता है। पुराने जमाने से इसे मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। यह बहुत घना, मुलायम, चमकदार, पीले रंग का धातु है। इंटरनैशनल मॉनेटरी फंड और बैंक फॉर इंटरनैशनल सैटलमैंट्स द्वारा स्वर्ण को एक वित्तीय मानदंड के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में इसका प्रयोग दंत चिकित्सा और इलैक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता हैं ।

साधारण प्रयोग के लिए शुद्ध स्वर्ण बहुत नरम है इसलिए शुद्ध सोने के गहने नहीं बनते हैं। गहने बनाने के लिए/इसे कड़ा या सख्त बनाने के लिए इसे सिल्वर, तांबा और अन्य धातुओं के साथ मिलाना पड़ता है। इस लिए आभूषण आमतौर पर 22 कैरेट अर्थात 916 शुद्धतायुक्त होते हैं। स्वर्ण विशेष रूप से नाइट्रिक एसिड में अधुलनीय है जो अधिकतर अन्यु धातुओं के लिए घुलनशील है। इसलिए नाइट्रिक एसिड को मदों में स्वर्ण की मात्रा होने या न होने की पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया जाता है और शुद्धता की परख के लिए 'एसिड टैस्ट' कहलाता है। सोना किलोबार या 100 ग्राम बार में आयात किया जाता है ।

सोने की शुद्धता का मानक

कैरेट	प्रतिशत	फाइननेस/शुद्धता/1000
24 कैरेट	99.99	9999.फाइन
24 कैरेट	99.9	फाइन 999
23 कैरेट	95.83	फाइन 958
22 कैरेट	91.66	फाइन 916
21 कैरेट	87.5	फाइन 875
18 कैरेट	75.0	फाइन 750
14 कैरेट	58.33	फाइन 583
9 कैरेट	37.5	फाइन 375

माप तौल : सोने का भार ट्रॉय आउंस या ग्राम में मापा जाता है। आपस में बदलने के लिए निम्नलिखित टिप्स याद रखने योग्य हैं :

01 तोला	11.664 ग्राम
01 ट्रॉय आउंस	31.104 ग्राम
01 किलोग्राम	32.150 ट्रॉय आउंस
01 ट्रॉय पाउंड(एलबी)	12 ट्रॉय आउंस
01 ट्रॉय आउंस (ओ्जैड)	20 पैनीवेट(डीडब्ल्यूटी)
01 ट्रॉय आउंस(ओ्जैड)	480 ग्रेन्स
01 ट्रॉय आउंस(ओ्जैड)	33.3 ग्राम
01 पाउंड(एलबी)	16 आउंस / 454 ग्राम
01 किलोग्राम	1000 ग्राम / 35 आउंस / 2.2 पाउंड(एलबी)

चाँदी

चाँदी का रसायनिक नाम एजी (Ag) है और यह एक नरम धातु है जिसका रंग सफेद है और विश्व में आभूषण, सम्पत्ति और बर्तनों के रूप में प्रयोग की जाती है। चाँदी चट्टानों में तॉबा, शीशा व सोने में मिली हुई मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। यह अधिकतर कनाडा, मैक्सिको, पेरु तथा अमेरीका में पाई जाती है। चाँदी अपने एक गुण के अनुसार किटाणुनाशक है। चाँदी बहुमूल्य धातु है और इसका प्रयोग पुरातन काल से हो रहा है। स्वर्ण की तरह ही चाँदी की भी हॉलमार्किंग होती है जिस की शुद्धता प्रतिशत व 1000 पर आधारित होती है जैसे एमएमटीसी के स्टर्लिंग सिल्वर उत्पादों की शुद्धता 92. 5 प्रतिशत या 925.0 तथा चाँदी के मेडालियन 999.0 शुद्धतायुक्त होते हैं। चांदी स्टैंडर्ड बार और ग्रेन्स के रूप में आयात होती है ।

"सांची" सिल्वर वेयर

एमएमटीसी के भारत में सभी महानगरों में अपने ब्रांड स्टर्लिंग सिल्वरवेयर (सांची) और रिटेल आभूषणों के शोरूम हैं। हम अपने थोक / कारपोरेट ग्राहकों के लिए सॉची सिल्वरवेयर अनन्य डिजाइनों में उनकी विशेष मांग के अनुसार विभिन्न तौल, आकार व साइज में फेब्रीकेट करवाकर उपलब्ध कराते हैं। सॉची सिल्वरवेयर के टेबलवेयर में गिलास, कटोरियां, टी सेट, डिनर सेट, ट्रे, थाली, जग आदि शामिल हैं। धार्मिक मदों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां व आकृतियां हैं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण भारत के लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार बनी होती हैं और पूजा के लिए प्रयोग में लायी जाती है जैसे लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, साई बाबा, शेरावाली माँ इत्यादि की मूर्तियां, छत्तर, चौकी, त्रिशूल, दीपक तथा लेम्प आदि। उपहार मदें – जैसे घड़ी, पैन, बॉक्स, तथा अन्य कई प्रकार की मदें शामिल हैं। खुदरा बिक्री तथा कॉरपोरेट ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एमएमटीसी सर्वथा प्रयासरत है।

दिल्ली तथा अन्य शहरों में एमएमटीसी के कई स्टॉकिस्ट / फ्रेंचाइजी विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हैं जहां एमएमटीसी के हॉलमार्कयुक्त स्वर्णाभूषण, सोने व चॉदी के मेडेलियन तथा सॉची सिल्वरवेयर उत्पादों की बिक्री की जाती है ।

सोने व चांदी के मेडालियन / सिक्के

शोरूम / बिक्री केंद्रों में 0.5, 1, 2, 5, 8, 10, 20, 50, 100 तथा 1000 ग्राम के सोने के सिक्के / मेडालियन तथा चाँदी के 10, 20, 50, 100, 250, 500 तथा 1000 ग्राम के विभिन्न आकार के सिक्के / मेडालियन की बिक्री की जाती हैं। उपर्युक्त सिक्के / मेडालियन एमएमटीसी द्वारा अपनी वर्कशॉप में तैयार किये जाते हैं जिनकी गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है ।

एमएमटीसी सोना, चाँदी, प्लेटिनम, पैलाडियम, कच्चे हीरे, ऐमरेल्ड, रूबी और अन्य सभी बहुमूल्य स्टोन के आयात के लिए भारत सरकार की प्राधिकृत एजेंसी है जो इसकी घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए भारत के ज्वैलरों को सप्लाई करती है ।

स्वर्ण / चांदी की परख व हॉलमार्किंग : सोने व चाँदी में बहुमूल्य धातु की आनुपातिक मात्रा का शुद्ध निर्धारण करना तथा उसका सामान्य

रूप से उस मद पर उल्लेख करना ही हॉलमार्क करना कहलाता है। हॉलमार्क इसकी शुद्धता की स्पष्टता प्रकट करता है और गुणवत्ता की प्रतिबद्धता दर्शाता है। हॉलमार्क योजना का उद्देश्य सोने की अनियमित गुणवत्ता के कारण ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। वर्ष 2003 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसमें एमएमटीसी को एक प्रतिष्ठित ज्वैलर एवं उपभोक्ता के तौर पर एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था और स्वर्ण/चाँदी तथा इनकी मदों की शुद्धता की परख करने के लिए बाद में एमएमटीसी के झंडेवालान, नई दिल्ली, अहमदाबाद व कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों में अस्सेयिंग व हालमार्क यूनिटों की स्थापना की गयी जो भारतीय मानक ब्यूरों से विधिवत प्रमाणित है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो को हालमार्किंग योजना के लिए प्राधिकृत किया था ताकि पब्लिक को सोने में मिलावट के प्रति सचेत किया जा सके ।

सोने व चाँदी की हॉलमार्क की गयी मदों पर निम्नलिखित पांच निशान अंकित होते हैं :

1. बी आई एस का तिकोणाकार निशान
2. शुद्धता/फाइननेस, जैसे 22 कैरेट के आभूषण पर 916 अंकित होगा
3. हॉलमार्क करने वाले केंद्र का लोगो/निशान
4. हॉलमार्क का वर्ष जिसे कोड वर्ण के रूप में अंकित किया जाता है जैसे वर्ष 2000 के लिए ए तथा 2001 के लिए बी तथा इसी क्रम मे आगे
5. ज्वैलर का लोगो/निशान

एमएमटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय/ बिक्री केंद्र : भारत तथा विदेशों में स्वर्ण प्रदर्शनियां आयोजित करने के अतिरिक्त एमएमटीसी के स्वर्ण/चाँदी मेडालियन मिंटिंग के लिए मेडालियन विनिर्माण यूनिट उपलब्ध है। कंपनी का राष्ट्रव्यापी घरेलू नेटवर्क 75 क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय, पोर्ट तथा फील्ड कार्यालयों, वेयरहाउसिज तथा खरीद केन्द्रों के माध्यम से सक्रिय है।

Balco Judgment: Landmark Decision of SC on Arbitration

Madhusudan Jena
Chief Manager (Law)

In case of Bharat Aluminum Company vs. Kaiser Aluminum Technical Services, (known as Balco judgment), the Hon'ble Supreme Court of India held that the Indian courts would not have jurisdiction with respect to arbitrations with 'seat outside India', either for the purposes of granting interim relief or with respect to entertaining a challenge to foreign arbitral awards in India.

The Supreme Court has held that Part I of the 1996 Act will henceforth not be applicable to any international commercial arbitration having 'seat outside India' irrespective of whether or not Part I has been expressly or impliedly excluded by the parties. This decision has thereby overruled, prospectively, the earlier decisions in Bhatia International vs. Bulk Trading SA and Venture Global Engineering vs. Satyam Computer Services Ltd.

The Arbitration and Conciliation Act, 1996 is divided into three parts: Part I deals with arbitrations which have their seat in India, Part II pertains to recognition and enforcement of foreign arbitral awards in India, and Part III deals with conciliation. The spheres of operation of Parts I and II were traditionally regarded as being distinct and mutually exclusive. However, the Supreme Court of India in Bhatia International ruled that:

'Part I is to apply also to international commercial arbitrations which take place out of India, unless the parties by agreement, express or implied, exclude it or any of its provisions.'

The rationale behind Bhatia International was that sec 2(2) of the 1996 Act, which provides that Part I 'shall apply where the place of arbitration is in India', was merely a clarificatory and inclusive provision. The Supreme Court in Bhatia International was also of the view that the parties would be without remedy if Part I was held not to be applicable to foreign seated arbitrations in

relation to the property or asset located in India.

Relying upon the principles in Bhatia International, the Supreme Court in the case of Venture Global held that unless Part I was specifically excluded, either expressly or impliedly, a foreign award can be challenged in India under sec 34 in Part I of the 1996 Act.

In case of Balco judgment, the Apex Court, while emphasizing the exclusive operations under Part I and Part II of the 1996 Act, held that the remedy to seek interim relief under sec 9 and the remedy to challenge an arbitral award under sec 34 could apply only if the seat of arbitration is in India. In view of the concept of seat, Part I (including the provisions underlying sec 9 and sec 34 of the Act), would apply to international commercial arbitrations seated in India and to domestic arbitrations, while Part II of the 1996 Act applies to international commercial arbitration seated outside India.

In relation to sec 48 of the 1996 Act, the Court held that the reference made to the court of the country 'in' which the award was made, ie the country of the seat, and the court of the country 'under' the law of which the award was made, do not confer concurrent jurisdiction. The objective is to provide for a second alternative, where the first is unavailable, ie where the country of the seat does not entertain a challenge to the award. Further, sec 48 of the 1996 Act does not confer jurisdiction to set aside an award but merely provides that a domestic court may refuse to enforce an award if the conditions in the provision are satisfied. The expression 'under the law which the award was made' refers only to the curial law of the country and not substantive law governing the substance of the agreement.

In relation to the enforcement of awards rendered in international commercial arbitrations held outside India, the Court held that such awards would only be subject to the jurisdiction of the Indian courts when such awards are sought to be enforced in India in accordance with the provisions contained in Part II of the 1996 Act.

The Court further held that, while Part I of the 1996 Act regulates an arbitration at all four stages of its life (namely the commencement of arbitration, conduct of arbitration, challenge to an arbitration award and the recognition or enforcement of the award), Part II of the 1996 Act has restrictive application in that it regulates an arbitration only at the stage of recognition and enforcement of the award.

The Balco judgment has only been given prospective application ie the law laid down in this case would apply only to arbitration agreements executed subsequent to the date of judgment (i.e. 6th September 2012). Therefore, in case of any existing agreement, arbitrations and disputes or proceedings currently pending (as on the date of the verdict) will continue to be governed by Bhatia International and subsequent decisions.

In the meanwhile, though two review petitions have been filed for review of the judgment, it ousts the Indian court's jurisdiction completely in foreign-seated arbitrations.

Jurists as Supreme Court Judges

Dr. O.P. Motiwal
Ex- CGM (Law)

Having entrusted the heavy responsibility on the Supreme Court of being a custodian of the liberties of the citizens, the members of the Constituent Assembly were very cautious in providing the high standard of selection of the judges of this temple of justice. They discussed the various provisions relating to this Court in great detail and with special interest as is evident from the debates themselves. The Constitution lays down that a person shall not be Qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and he has been for at least five years a judge of a High Court or of two more such courts in succession or has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession or is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.

Since the establishment of the Supreme Court, all its judges with the exception of one, have been appointed from the bench, though some of them had been practising lawyers before their elevation the bench. This exception was in the case of Mr. Justice S. M. Sikri, who was the Advocate-General of Punjab and had earned a great reputation in the field of law and advocacy. He has lived up to his reputation. However, in spite of a clear provision in the Constitution, not a single jurist has been appointed a Supreme Court judge.

"Jurist" , according to Corpus Juris Secondum, "is a term which answers to the Latin word 'Jurisperttus' and signifies one who is versed or skilled in law, one who is skilled in the civil law, or the law of nations. This term is now usually applied to those who have distinguished themselves by their writings on legal subjects".

In order to appreciate the spirit behind the provision in the Constitution for the appointment of jurists as judges of the Supreme Court, it is necessary to go through the debates of the Constituent Assembly. Sub-clause (c), providing for the appointment of a distinguished jurist as a Supreme Court Judge, did not find a place in Article 103 of the Draft Constitution. Originally the Drafting Committee had made only judges of five years experience of a State High Court and advocates of ten years standing, eligible for Supreme Court judgeship, but when this article was taken up for discussion in the Constituent Assembly on May 24, 1949, Shri H.V. Kamath tabled an amendment to clause (3) of Article 103, making a distinguished jurist eligible for appointment as a judge of the

Supreme Court. He said that the object of his proposed amendment was to open a wider field of choice for the President in the matter of appointment of judges of the Supreme Court.

He further said: *"The House will see that the Article as it stands restricts the selection of judges to only two categories... I am sure that the House will realize that it is desirable, nay it is essential, to have men, or for the matter of that women, who are possessed of outstanding legal and juristic learning. In my humble judgment, such are not necessarily confined to judges and advocates."*

Shri Kamath further added that his argument was based on the provision relating to the qualifications for judges of the International Court of Justice at the Hague. He was perhaps referring to article 6 of the Statute of the Hague Court, which provides that "Before making these nominations (i.e., of judges) each national group is recommended to consult its highest court of justice, its legal faculties and schools of law, and its national academies devoted to the study of law".

Shri M. Ananthasayanam Ayyangar observed:

"I agree with my honourable friend Mr. Kamath ... A person may enter the profession of law straight away. He might be a member of a law college or be a Dean of the Faculty of Law in a University. There are many eminent persons, there are many writers, there are jurists of great eminence. Why should it not be made possible for President to appoint a jurist of distinction, if it is necessary."

Further, he pleaded that out of the proposed seven judges, one must be a jurist (Originally the numbers of Supreme Court Judges was fixed at seven, but later it was increased). The amendment of Shri Kamath was adopted by the Constituent Assembly, thereby enabling the President to appoint a person as a judge of the Supreme Court, who in his opinion, was a distinguished jurist.

It may be pointed out here that the Constitution does not make any provision for the appointment of a jurist as a High Court judge, perhaps because for a distinguished jurist the framers of the Constitution considered the judgeship of a High Court not good enough. It was for the highest court of justice in the country that they thought of appointing distinguished jurists. The desirability of such appointments has been appreciated and acknowledged by the major democracies of the world and countries like United States of America, Great Britain, France and West Germany have constitutional provisions or conventions regarding the appointment of distinguished jurists as judges of their highest courts. Superior judiciary in France and West Germany is recruited exclusively from the academic jurists, having no judicial experience at all. Italy, Brazil and Panama also have provisions to the effect of enabling outstanding jurists to be appointed as judges of the highest court.

The American Constitution does not lay down any qualifications for the appointment of judges in the Supreme Court. The silence of the written law, both constitutional and statutory, implies that, so far as the world of the law is concerned , the President is not restricted in any

way in his choice of a judge of the Supreme Court. He can even appoint a person who has no legal background. He is, however, required to obtain the consent of the Senate for the appointments he makes. The field of choice of the President is very wide. Political considerations have always played an important role in the selection of the Supreme Court justices. It is rare for the President to appoint a man to the nation's highest court who is not a member of his own political party. But there have been a few exceptions in such appointments in the long history of the American Supreme Court. President Eisenhower strongly pleaded for the consideration of men with judicial experience for appointments to the Supreme Court. Bills at times have been introduced in the Congress to give effect to such a view, and in recent years a growing number of appointments to the federal bench have been made from among the members of the bar but not engaged in ordinary practice, or jurists working as Professors of Universities. If judicial experience had been a prerequisite, most of the eminent judges such as Marshall, Story, Taney, Miller, Bradley, Hughes, Brandies, Stone, Black, Frankfurter, Jackson and Warren, would not have found a place on the bench of the Supreme Court in U.S.A.

Justice Frankfurter was Law Professor at the Harvard University before his appointment in the Supreme Court. If one reads his decisions, they are struck by his ability and great learning of law. Chief Justice Hughes before he was selected for appointment to the bench had held the office of Governor of New York and was at one time a candidate for Presidentship. Justice Hugo L. Black, Harold H. Burton and Sherman Minton served as United States Senators before they were appointed to the Court. Even Chief Justice Warren, who had been a Senator and Governor of California for about eleven long years, did not have any judicial background at the time of his appointment.

Justice Frankfurter while discussing the need of judicial experience for the office of a Supreme Court judge went so far as to say that correlation between prior judicial experience and fitness for the function of the Supreme Court is zero.

The Italian Constitution has prescribed that the judges of the Constitutional Court are selected from judges, University professors of law and lawyers. In Panama too, Professors of Law have been made eligible for appointment as judges of the Supreme Court of Justice under Article 166 of the Constitution.

In England no qualification has been prescribed for the post of Lord High Chancellor under any law, but in practice the

Sovereign appoints to this high office a person recommended by the Prime Minister from amongst the members of the Bench or such members of the Bar who hold or have held the office of Attorney-General or Solicitor-General. But on numerous occasions, persons having no judicial background have occupied this post, such as Lord Haldane from 1912 to 1915 and again in 1924, Lord Sankey from 1929 to 1935, Lord Maugham from 1938 to 1939, and Lord Sunords in 1951.

The Constitution of the United States of Brazil prescribes that the justices of the Federal Supreme Court are to be appointed with the concurrence of the Federal Senate from among Brazilians of notable juridical wisdom and spotless reputation.

In the erstwhile USSR, judges of the Supreme Court were elected and no qualification was prescribed for their appointment and every effort was made to recruit them from among the communists. The judges of Supreme Court were not required to be judges of lower courts or members of the bar. The Soviet Minister for Justice in 1947 had remarked:

The number of specialists graduated from higher or secondary schools who are employed in the judicial bodies controlled by the Ministry of Justice is insignificant ... There are many regions, provinces, and autonomous republics where all the people's judges have no higher education.

About 64% of judges in Russia lack any legal training whatsoever. The soviet judicial system and appointment of judges is quite typical and by citing its example, it is not proposed that our judges should also be elected or that they need not have the necessary legal education or background. What is implied is that there is an advanced country where judges are effectively dispensing justice without having any formal legal training.

When in so many countries the system of appointment of jurists to the highest judicial tribunals has worked satisfactorily, it is not understood what considerations have stood in the way of the appointment of jurists as Supreme Court Judges in India, in spite of the fact that they have been made eligible for appointment under the Constitution by article 124(3)(c). It appears all the more surprising in the background of the debates in the Constituent Assembly on the subject referred to above. Had the system of appointment of jurists not proved satisfactory in the countries where it is in vogue, they would have certainly given it up. Jurists have proved that they are eminently fit for appointment as judges. In India we do have some jurists of very high caliber and their suitability for appointment to the bench of the Supreme Court can hardly be questioned. Some of the top Indian jurists who have established a name for learning and knowledge not only in India but in other countries also are working as professors in Indian Universities or are engaged in legal research in India or abroad. It is high time to make use of the provision in Article 124(3)(c) of the Constitution, which has been lying otiose.

ट्रेड यूनियन का उद्देश्य

डी. सी. शर्मा
महासचिव, फेडरेशन ऑफ एमएमटीसी स्टाफ यूनियंस

ट्रेड यूनियन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की रक्षा, उनकी हर मुश्किल को सुलझाना। ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ के अन्तर्गत कामगारों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे संस्था में कम से कम 7 सदस्य के साथ ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराकर उस को प्रबंधन के साथ मान्यता दिलाये। संघ के प्रतिनिधि, प्रबंधन के साथ एक संगठन मे काम करने वाले लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दो पर चर्चा कर उत्पन्न हुए किसी भी मतभेद को खत्म करने के लिए नियोक्ताओ के साथ बातचीत कर उन मुद्दों का समाधान करते हैं जिसमें कामगारों के काम के घंटे, अवकाश और प्रथाओं मे परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सदस्य को मिलने वाली राशि दिलाना, उनके वेतन–मान व अन्य बिंदुओं पर प्रबंधन के साथ संवाद कर उस का निष्पादन करना, पेय जल आदि शामिल हैं।

कामगारों को प्रभावित करने वाले नियमों मे अपनी आवाजः ट्रेड यूनियन कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, उनके रोजगार, मजदूरी, कार्य समय के साथ उनकी प्रमोशन एवं स्थानांतरण के साथ–साथ कर्मचारियों के चयन में अपनी पकड बनाने का मौलिक अधिकार रखते हैं जिससे कि प्रबंधन कामगार विरोधी नीति ना बना सके।

सदस्यों को सेवाए उपलब्ध कराना : ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के शिक्षा और प्रशिक्षण, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, व अन्य मुद्दों पर अपने सदस्यों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं जिससे सदस्यों को कई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शिक्षित होने का मौका मिलता है जिसका लाभ सदस्य एवं संगठन दोनों को मिलता है।

कानूनी सहायताः ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों को समय–समय पर कानूनी सहायता, आवास और कर्ज जैसे व्यतिगत मामलों मे भी मदद कर सकते है। संकट के समय सदस्य को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी व रोजगार में अपने यूनियन के पुराने सदस्य को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

संस्था मे यूनियन का महत्व

किसी भी संस्था में एक मजबूत यूनियन की मान्यता नितांत जरूरी हैं जिस से वहां कार्यरत कर्मचारी के मुद्दों पर सामूहिक सौदेबाजी को अधिक प्रभावशाली बना कर कामगारों के मुद्दों का हल किया जा सकता है, जिससे संस्था प्रबन्धन से अनेक समस्याओं का शांति पूर्ण हल निकलता है। ट्रेड यूनियन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कामगारों और प्रबन्धन के बीच प्रभावी संवाद मे सहायक होते है, जिससे कई एक प्रमुख मुद्दों पर संघर्ष व मतभेद नही पनपता। केंद्रीय यूनियनों का हिंदुस्तान के कल–कारखानों व कई व्यापारिक इकाईयों आदि में विशेष स्थान है। इन यूनियनों का श्रमिकों के वेतनमान समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विशेष मुद्दों पर अपने सदस्यों के लिये पाठ्यक्रम का आयोजन कराते हैं जिससे कामगार शिक्षित हो सके। इसके अतिरिक्त ये यूनियन समय–समय पर सरकार से संवाद के साथ कामगारों के काम के क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूरों की आवाज सरकार तक पहुचाते हैं और समय–समय पर सरकार को जगाने के लिये सांकेतिक धरना या प्रदर्शन का भी सहारा लेते हैं। श्रमिकों की आवाज को मजबूती के साथ प्रबंधन और सरकार के सामने रख कर उनसे संवाद करते हैं।

ट्रेड यूनियन के माध्यम से श्रमिकों का आर्थिक विकास :–

1 कार्यकर्ताओं की भर्ती और चयन में मदद करना।

2 कर्मचारियों में अनुशासन पैदा करना।

3 तर्कसंगत ढंग से औधोगिक विवादों का निपटान करना।

4 सामजिक समायोजन की मदद से श्रमिकों को नया करने के लिये खुद को समायोजित करना।

5 काम करने की स्थिति, नये नियमों और नीतियों पर अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले श्रमिकों में अहम रोल अदा करना।

ट्रेड यूनियन समाज का एक हिस्सा है और इस तरह यूनियन राष्ट्रीय एकता मे महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है। औद्योगिक विवादों की संख्या को घटा कर राष्ट्रीय एकता बनाने में मददगार साबित करना तथा श्रमिकों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित कर मिसाल बनाने का एक माध्यम है।

नेगोसियशन : संघ के प्रतिनिधि, प्रबंधन के साथ एक संगठन में काम कर रहे श्रमिको को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जहाँ प्रबंधन और यूनियन के सदस्यों में मतभेद हो सकता है, पर चर्चा करते हैं। ट्रेड यूनियन इन मतभेदों को निपटाने व समाधान खोजने के लिये नियोक्ताओं के साथ बात–चीत करती है। वेतन, काम के घंटे, अवकाश और काम प्रथाओं में परिवर्तन पर कई एक कार्यस्थलों में संघ व नियोक्ता के साथ बात–चीत करने का अनुबंध रखते हैं। कई संघठनों में सामूहिक सौदेबाजी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये संघठन के विभिन्न व क्षेत्रीय ऑफिस में मौजूदा यूनियन अपनी सभी यूनियनों का एक महासंघ बनाते हैं, जिससे संघठन के प्रत्येक क्षेत्र में तैनात श्रमिकों की मूल भूत मांगों का निष्पादन करने के लिये महासंघ अपने साथ अपनी सहयोगी यूनियनों का मत ले कर प्रबंधन के साथ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से श्रमिकों के हितों को सुरक्षित कराते हैं। देश में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियनों की भागीदारी सर्वाधिक है।

श्रमिकों को प्रभावित करने वाले निर्णयों मे यूनियन की भूमिका : कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा निर्धारित करना, जैसे कर्मचारियों के वेतनमान, रोजगार की अवधि, एवं इनके अतिरिक्त प्रबंधन की नीतियों पर प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन के बीच उनका मत रखना।

ट्रेड यूनियन के कार्य

ट्रेड यूनियन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न रणनीति इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्यतः

सौहार्दपूर्ण कार्य : ट्रेड यूनियन जरूरत के समय प्रदर्शन के माध्यम से प्रबन्धन को सहयोग दे कर अनुकूल औद्योगिक सम्बंधों को कायम कर अपने सदस्यों की शिक्षा और सहमति को बढ़ावा दे कर औद्योगिक शांति का प्रयास करते हैं। ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के मनोबल मे सुधार के लिये कल्याणकारी उपाय अपना कर उनमे आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने (सदस्यों) को कानूनी सलाह भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कल्याणकारी उपायों के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, पढ़ने के लिए कमरे, इन–डोर, आउट डोर खेलों को बढ़ावा और अन्य मनोरंजक सुविधाओं के लिए प्रबन्धन से बात करते हैं। कुछ ट्रेड यूनियन पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है। यह सभी गतिविधि को सौहार्दपूर्ण भाईचारा कोश कहते हैं जो कि यूनियन अपने सदस्यों व बाहरी लोगों से दान स्वरूप लेती है।

ट्रेड यूनियन में शामिल होने के कारण

श्रमिक अपने हक को प्रबंधन से प्राप्त करने में अपने नियोक्तों की तुलना में बहुत कम सौदेबाजी कर सकता है; इस के अभाव में रोजगार व मजदूरी व अन्य शर्तों से संतुष्ट न होने पर उसके पास एक रास्ता बचता हैं कि वह नौकरी छोड़ दूसरा रोजगार तलाशे जिसकी वजह से उस को अनेक वित्तीय नुकसान सहन करना पड़ता है। इसलिए यूनियन में भागीदारी से श्रमिक को वह हक मिलता है जिससे वह नियोक्ता पर यूनियन के साथ मिल कर कार्यवाही कर सके।

भेदभाव को कम करना : श्रमिकों के वेतन, काम, पदोन्नति आदि विषय संगठन मे काम करने वाले श्रमिकों को अत्यधिक व्यक्तिपरक होते हैं। संगठन मे एक अधिकारी लम्बे समय तक काम कर कई एक बार प्रबंधन को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार संघठन मे एक व्यक्ति विशेष को चुनना और श्रमिकों के बीच भेदभाव की भावना को जन्म देता है, जिसकी वजह से संस्था मे भ्रष्टाचार पनपता है। इन सभी को दुरुस्त करने के लिए ट्रेड यूनियन प्रबंधन से ऐसी नीतियों को लागू करने पर जोर देता है जिसके अन्तर्गत समानता हो। ट्रेड यूनियन प्रबंधन की नीति पर नजर

रख कर जहां कही भी कुछ गलत होता है वहां आवाज उठाने का अधिकार रखता है।

सुरक्षा की भावना : श्रमिकों को भरोसा होता है कि अगर वे यूनियन के सदस्य बनते हैं तो यूनियन के माध्यम से वे अपने को महफूज़ महसूस करते हैं; जैसे सेवा, दुर्घटना, चोट, बीमारी, रोजगार जैसे खतरे और आय पर असुरक्षा की विभिन्न प्रकार से पर्याप्त सुरक्षा पाने के लिए यूनियन एक कारगर तरीका है।

भागीदारी : किसी भी यूनियन की

सदस्यता श्रमिकों को हक देती है कि वो श्रमिकों को प्रभावित करने वाले मामलों में प्रबन्धन मे भागीदारी करे तथा संघ के बीच प्रबंधन के साथ सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिकों के हित मे निर्णय करा सके।

अपनत्व की भावना : बहुत से श्रमिक यूनियन के सदस्य साथियों के सामूहिक दबाव से यूनियन सदस्य बनते हैं। अगर कोई श्रमिक यूनियन का सदस्य नहीं बनता तो उसके कार्यस्थल पर असहयोग के साथ अन्य श्रमिकों के बीच उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर एक संघ का सदस्य अपने आप को सम्मानित महसूस करता है तथा अपने अन्य साथी कर्मचारियों की आँखों में रह कर किसी भी विषय में यूनियन से चर्चा करने का हक रखता है जो उनमें अपनेपन की भावना जगाता है।

(आत्म)अभिव्यक्ति के लिये मंच : आत्म अभिव्यक्ति ज्यादातर लोगों के लिये बुनियादी मानव ड्राइव है; श्रमिक अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं व श्रमिक यह भी चाहते हैं कि प्रबंधन उनकी बात सुने। ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों को एक साझा मंच प्रदान करती है जहां हर श्रमिक के विचार और उठाये गये विषयों पर विचार विमर्श किया जा सके। इस प्रकार के मंच न होने की सूरत में सदस्य यूनियन से मांग करते हैं कि ऐसे मंच का आयोजन किया जाये जहां कामगार अपने विचार रख सकें। यूनियन प्रबंधन के साथ अपने श्रमिकों के विचार व सुझावों को लेकर सामूहिक आवाज से प्रबंधन द्वारा नीतिगत निर्णय लेते समय प्रबंधन को अपने मत से अवगत कराते हैं।

रिश्तों की बेहतरी : कार्मिकों का यूनियन में शामिल होने के लिये एक और कारण यह है कि कर्मचारी यूनियन, नियोक्ता, संघों में उचित रख–रखाव के लिये पर्याप्त मशीनरी और महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में यूनियन एक कड़ी के रूप मे मददगार होती है; श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच में जिससे किसी भी समस्या का समाधान शांति पूर्ण ढंग से किया जा सके। आपस में विवाद न पनपे और आपस में श्रमिक व प्रबंधन के बीच मधुर सम्बंध स्थापित हो, इसके लिये भी यूनियन बेहतरीन प्रयास करती है।

भारत मे ट्रेड यूनियन

भारत में ट्रेड यूनियन पश्चिमी देशों की तुलना में काफी विलम्ब से विकसित हुआ। भारत की ट्रेड यूनियन आंदोलन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम चरण (1850–1900) : ट्रेड यूनियन के शुरुआती दौर मे श्रमिकों के काम और रहन–सहन की स्थिति बहुत ही खराब थी और उन्हें काम पर अधिक घंटे तक लगाया जाता था। पूंजीपति केवल उनकी उत्पादकता और उन से होने वाले लाभ प्राप्ति मे ही रुचि रखते थे, इस के बदले मे मजदूरी बहुत ही कम थी और सामान्य मजदूर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारतीय कपड़ा मजदूरों के काम के घंटे व अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए भारतीय कारखाना अधिनियम सन 1881 मे लागू किया गया था

जिसके परिणाम स्वरूप बाल मजदूरी निषिद्ध किया गया।

ट्रेड यूनियन के आंदोलनों के दौर में श्रमिकों की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं होने पर सन 1881 भारतीय फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया गया। दो दशकों से सन 1880 तक सभी औद्योगिक शहरों में काफी हड़ताल प्रदर्शन किये गये और आंदोलन की शक्ति से एकता तो कायम हुई परंतु किसी ट्रेड यूनियन की स्थापना नहीं हो पाई और ऐसे ही बॉम्बे मिल असोसियेशन जैसे छोटे संघ का जन्म हुआ।

दूसरा चरण (1900– 1946) : इस चरण की विशेषता थी ट्रेड यूनियन और मजदूर वर्ग की राजनीति आंदोलनों में विकास। सन 1918 और 1923 के बीच देश में कई यूनियन अस्तित्व में आई। अहमदाबाद में महात्मा गाँधी के मार्ग दर्शन में, स्पिनरो यूनियन और बुनकर यूनियन की तरह व्यवसायिक संगठनों में यूनियन का गठन हुआ। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में इन यूनियन्स ने हड़तालों को सत्याग्रह में बदल दिया। औद्योगिक संघ में इन यूनियन्स को सन् 1920 के टेक्सटाइल लेबर असोसियेशन के रूप में जाना जाता है।

सन 1920 मे प्रथम नेशनल ट्रेड यूनियन संघठन (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)) की स्थापना की गई। और इस संगठन के नेताओं ने कई राष्ट्रीय आंदोलनों मे भाग लिया। सन 1926 में बना ट्रेड यूनियन कानून 1927 मे लागू हो गया; इस कानून को लाने में एन. एन. जोशी ने अथक प्रयास किया। सन 1928 के दौरान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन (AITUF) का गठन किया गया।

तीसरा चरण : तीसरा चरण 1947 में स्वतंत्र भारत के उदय के साथ शुरू हुआ। देश के विभाजन ने ट्रेड यूनियन आंदोलन, विशेष रूप में बंगाल और पंजाब, को प्रभावित किया और सन् 1949 मे चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संघठनों का गठन हुआः–

1 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

2 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

3 हिन्द मजदूर संघ

4 संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस

भारत मे मजदूर वर्ग आंदोलन भी राजनीति दलों की तर्ज पर विभाजित किया गया जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन (इंटक) ने कांग्रेस पार्टी के ट्रेड यूनियन का चिन्ह हाथ, एटक भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के अलावा सफेद कालर कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और बैंकिंग, बीमा और पेट्रोलियम व अन्य उद्योगों मे यूनियन हैं। इस के अतिरिक्त वर्तमान में भारत में बारह केंद्रीय संघठन हैं ।

1 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)

2 भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

3 भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)

4 हिन्द मजदूर किसान पंचायत (एचएकेपी)

5 हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)

6 फ्री ट्रेड यूनियन के भारतीय संघ (आईएफएफटीयू)

7 भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

8 भारतीय ट्रेड यूनियन की नेशनल फ्रंट (एनएफआईटीयू)

9 राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ)

10 ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द (टीयूसी)

11 संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी)

12 संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी लोक सभा)

उद्योगों में मधुर संबंध बनाए रखने और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा देने के लिए और प्रबंधन व यूनियन संगठन में सहयोग प्रदान करने के लिए अनुशासन संहिता का मूल उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. उद्योगों मे शांति और व्यवस्था बनाए रखना
2. प्रबंधन और रोजगार के सभी स्थान पर रचनात्मक आलोचना
3. उद्योग में काम ठहराव से बचना
4. एक पारस्परिक ढंग से सहमत प्रक्रिया के माध्यम से विवादों और शिकायतों को समाप्त करना
5. मुकदमेबाजी से बचना
6. ट्रेड यूनियन का स्वतन्त्र विकास देना
7. औद्योगिक संबंध संचालन
8. औद्योगिक संबंध संचालक नियमों और विनियमों के किसी भी प्रकार के उलंघन को समाप्त करना

भारत के प्रधानमंत्री देश को चौमुखी विकास देने की लिए **'मेक इन इंडिया'** औद्योगिक क्रांति देश में लाना चाहते हैं जिस से देश को समावेशी विकास मिल

सके जिसकी हर भारतीय सराहना करता है। मेरा मानना है इस प्रगतिशील कदम में सरकार को कामगारों के हितों को सर्वोपरि रख कर श्रम कानून में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ कामगारों के काम के घंटे के साथ उनके मौलिक अधिकार व सामाजिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो सके।

जय हिन्द जय भारत।

GOODBYE TO A BELOVED TEACHER / MENTOR

There are no words, words befitting.
To describe a man so full of blessings.
A heart so big, had shades so many,
A singer, an athlete, a guiding hand to many.
That big warm hug and welcoming smile,
That booming voice welcoming you from beyond a mile,
Words and years can not describe his dedication.
The fruits can be seen here and beyond nation.
Together and forever we will remain
Your pupil and children through sun and rain,
We will always feel your blessing with each new step we take.

Vinay Varghese
S/o Salomi Varghese
C.O.M., RO- Ahmedabad

DF of the Year Award 2014

Director (F) Sh. M.G. Gupta was honoured by Bharat Nirman, an NGO engaged in promotion of Indian Culture & Traditions since 1980, with the 'DF of the Year Award 2014' under their new series 'Master of the Year Awards 2014'. The event was held on 31st December 2014 at the India Islamic Culture Centre, Lodhi Road, New Delhi.

एमएमटीसी कालोनी में दशहरे का आयोजन

त्रिभुवन महतो
अध्यक्ष / आरडब्ल्यूए

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एमएमटीसी आरडब्ल्यूए द्वारा एमएमटीसी कालोनी, नई दिल्ली, में असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे के त्योहार का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन स्थल पर खाने–पीने की चीजों के दो बड़े स्टाल भी लगाए गए थे। इस अवसर पर श्रीमती आरती मेहरा, पूर्व महापौर, दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एमएमटीसी कालोनीवासियों के अलावा आसपास के सभी इलाकों से भारी संख्या में लोग दशहरे को देखने के लिए उपस्थित थे।

इस अवसर पर रंग–बिरंगी आकर्षक आतिशबाजी व विधिवत दशहरा पूजन के बाद रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पुतलो के दहन के कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि श्रीमती आरती मेहरा तथा आरडब्ल्यू के वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह बिचा के कर कमलों के द्वारा किया गया। अंत में एमएमटीसी प्रबंधन द्वारा कालोनीवासियों के लिए उपलब्ध करवाए गए 10 ग्राम के 20 सिल्वर सिक्कों का लक्की ड्रा के माध्यम से वितरण किया गया।

उपस्थित मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया तथा इस कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की जिससे हमें अगले वर्ष भी दशहरे का आयोजन करने का संबल मिला। ज्ञात हो कि उपरोक्त कार्यक्रम एमएमटीसी प्रबंधन के सहयोग के बिना संभव नहीं होता अतएव हम सभी कालोनीवासियों व अपनी कमेटी की ओर से एमएमटीसी प्रबंधन का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिससे हमें समर्पण के साथ कार्य करने हेतु उत्साह मिलता है। इस कार्यक्रम के शान्तिपूर्ण आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम दिल्ली पुलिस के प्रति अपना आभार प्रकट करतें हैं।

Superannuations at CO

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Raj Kishore

Shri Raj Kishore	Sr. Office Manager
Date of Appointment	09/07/1979
Date of Retirement	31/10/2014
Service Rendered	Over 35 years

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Virender Singh

Shri Virender Singh	Field Officer
Date of Appointment	13/07/1979
Date of Retirement	30/11/2014
Service Rendered	Over 35 years

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Ram Kumar

Shri Ram Kumar	Grade III
Date of Appointment	11/04/1983
Date of Retirement	31/12/2014
Service Rendered	Nearly 32 years

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Ram Saran

Shri Ram Saran	Grade III
Date of Appointment	19/01/1982
Date of Retirement	31/12/2014
Service Rendered	Nearly 33 years

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Bhagat Ram

Shri Rajeev Jaideva, Dir (P), with Shri Kanhaiya Lal

Shri Bhagat Ram	Chief Office Manager
Date of Appointment	12/06/1973
Date of Retirement	31/12/2014
Service Rendered	Over 41 years

Shri Kanhaiya Lal	Manager
Date of Appointment	24/09/1976
Date of Retirement	31/12/2014
Service Rendered	Over 38 years

गोवा में सेवा निवृत्ति

मंदा वल्वईकर
वरिष्ठ कार्यालय प्रबंधक

श्री मुहम्मद इकबाल, मुख्य कार्यालय प्रबंधक, द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.09.2014 को कार्यालय में उनकी सेवा निवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया।

इसकी अध्यक्षता करते हुए श्री वर्नन डिसिल्वा, प्रबंधक (कार्मिक), ने उनकी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि, श्री मुहम्मद इकबाल बहुत ही मिलनसार होने के साथ–साथ प्रसन्नचित व्यक्तित्व के धनी थे। श्री इकबाल ने एमएमटीसी की प्रशंसा करते हुए ये कथन किया की जाते जाते एमएमटीसी ने पदोन्नति देकर मुझे विदा किया है, इसलिए मै एमएमटीसी का हमेशा आभारी रहूंगा।

सेवा निवृत्त श्री मुहम्मद इकबाल को फूलों की माला पहनाते श्री वर्नन डिसिल्वा, प्रबंधक (कार्मिक), बाये बैठे श्री लक्ष्मण पोरोब, प्रबंधक (सतर्कता)।

CMD Sh. Ved Prakash being welcome by CGM, RO- Kolkata

CMD's Visit to RO Kolkata

S V Kalve
AGM (PMD), RO Kolkata

Shri Ved Prakash, CMD, recently visited RO - Kolkata. Shri J Kishan, CGM, welcomed the CMD and briefed him on the overall activities of RO - Kolkata and highlighted the performance of the RO. A newly renovated Board Room was inaugurated at the hands of CMD. In his address to all RO officials, CMD emphasized the need for achieving the company goals and also advised on the special importance of customer satisfaction, repeated customer contact, upgradation of product and individual knowledge, etc. in order to keep pace with emerging market trends. CMD was kind enough to give patient hearing to the issues brought to his knowledge during the visit. The address of CMD to RO was quite encouraging and motivating in lifting the spirits of the employees.

MMTC SC/ST Employees Welfare Association, RO - Kolkata unit also felicitated the CMD.

CMD Sh. Ved Prakash inaugurating the new Board Room

CMD being felicitated by Sh. S.V. Kalve on behalf of SC/ST Welfare Association of RO - Kolkata

On 31st December 2014, Shri D.S. Dhesi, IAS, relinquished office of CMD of MMTC to take of his new assignment as Chief Secretary, Haryana. Shri Ved Prakash, Director (Marketing), assumed the additional charge of Chairman-cum-Managing Director. On 30th December 2014, a farewell program was organized for Shri Dhesi where the senior management of MMTC presented him with a memento.

Sh. Ved Prakash has taken over charge as Chairman and Managing Director w.e.f. 19.03.2015.

On 11th December 2014, Mr. Vladimir Putin, President of Russia, and Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, had an interaction with top 20 CEOs of India and Russia at Hyderabad House. Shri D.S. Dhesi, IAS, then CMD of MMTC, was one of the 20 CEOs from the Indian side.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का संदेश

श्री वेद प्रकाश ने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है

प्रिय साथियों,

मुझे एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करते समय हार्दिक प्रसन्नता है। मैं आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने सामूहिक प्रयास, कड़ी मेहनत तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से कंपनी को पिछले कुछ वर्षों में देखी गई अनिश्चितताओं से उबार कर नई उंचाइयों तथा गरिमा तक ले जाएंगे।

चुनौतियों से भरे व्यापार के इस वर्तमान परिवेश में हमें अपने प्रयासों में दुगुनी शक्ति दिखानी होगी जिससे कि हम अपने पिछले पचास वर्षों में अर्जित की गई साख का पूरा लाभ उठाते हुए कंपनी को नई उंचाइयों तक ले जा सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जहां एक ओर अपनी वर्तमान व्यापारिक गतिविधियों की रणनीतियों को सशक्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा वहीं दूसरी ओर हमारे व्यापारिक मॉडल के अनुसार व्यवसाय में विविधीकरण के नए अवसरों के क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा।

मैं एमएमटीसी को एक आधुनिक व्यापारिक संगठन के रूप में विकसित करने तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक अग्रणी उपक्रम बनाने के लिए आप सभी के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक 23.03.2015